ned by the technical considerations, including the availability of gas and other infrastructural facilities.

मैक्सिको में आयोजित विश्व जनसंख्या सम्मेलन

134. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 अगस्त, 1985 को मैक्सिको शहर में आयोजित विश्व जनसंख्या सम्मेलन में साधारण शिक्षा, विशेषत: महिला शिक्षा और सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के समुचित प्रचार और विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किए गये प्रस्ताव को मूर्त रूप देने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) अगस्त, 1984 में मैक्सिको सिटी में आयोजित अन्तरराष्ट्रीय जनसंख्या सम्मेलन में महिलाओं की शिक्षा के स्तर को बढ़ाने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के अन्तर्गत जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया था । इसमें उन देशों से भी, जहां अभी भी बहुत-सी अशिक्षित महिलायें हैं, जन शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिए पूरक प्रयास करने का अनुरोध किया गया था । ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को समग्र स्वास्थ्य परिचर्या के अंग के रूप में जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं जिन्हें सातवीं पंचवर्षीय योजना में सुदृढ़ किया जा रहा है। महिला साक्षरता की सुविधाओं को भी बढ़ाया जा रहा है।

स्कूलों और कालेजों में "सहकारिता" को एक विषय के रूप में शुरू किया जाना

135. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग में शिक्षा सलाहकार और स्कूलों और कालेजों में सहकारिता को एक विषय के रूप में किये जाने संबंधी समिति के अध्यक्ष, श्री डी०पी० नायर ने 1978 के आरम्भ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था और उसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि देश के नागरिकों को सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनाने और छात्र समुदाय के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के वास्ते स्कूलों में सहकारिता को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिये, यदि हां, तो उनके द्वारा दिये गए सुझावों का ब्यौरा क्या है, जिससे कि इस विषय को लोकप्रिय बनाया जा सके सके;

(ख) सरकार ने किस प्रकार सहकारिता के बारे में सैद्धांतिक और व्यावहारिक पाठ्यक्रम तैयार किये है; किन-किन राज्यों में इन पाठ्यक्रमों को शुरू कर दिया गया है और शेष राज्यों में इस विषय को शुरू करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है;

(ग) क्या यह सच है कि यह मामला 107 विश्वविद्यालयों को उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए भेजा गया था और उनमें से केवल 31 विश्वविद्यालयों ने उत्तर भेजे हैं, यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस योजना को तेजी से लागू करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

शिक्षा मंत्री (श्री के० सी० पन्त) : (क) 4-11-1975 को भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता संघ की सहकारिता प्रशिक्षण समिति (जो अब राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद के नाम से जानी जाती

है) ने योजना आयोग के शिक्षा सलाहकार, श्री डी० पी० नायर की अध्यक्षता में स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में सहयोग के शिक्षण से संबंधित एक विशेषज्ञ दल गठित किया । दल ने वर्ष 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । दल की सिफारिशों का विवरण में संक्षिप्त रूप में उल्लेख किया गया है ।

(ख) और (घ) सरकार इस बात से सहमत है कि सहयोग से सम्बन्धित शिक्षा वांछनीय है । तथापि स्कूलों का व्यापक रूप से प्रबन्ध तथा उनकी देखरेख मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। रा० शै० अनु० तथा प्र० परिषद ने राष्ट्रीय स्तर पर दस वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यचर्या का ढांचा तैयार किया है और इसके अनुसरण में विभिन्न विषयों में पाठ्य-विवरण तैयार किए है। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञानों के विषय शामिल किए गए। विषयों में सहयोग भी एक विषय है । राज्य रा०शै० अनु० तथा प्र० परिषद को पाठ्यचर्या और पाठ्य विवरण को अपनाने/उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए स्वतंत्र हैं ।

गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और मिजोरम के शिक्षा बोर्डों ने सूचित किया है कि उनके राज्यों के स्कूलों की कुछ कक्षाओं में सहयोग विषय पढ़ाया जा रहा है । गुजरात में कक्षा 10 में इसे अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है और अन्य राज्यों में इसे वैकल्पिक अथवा अन्य विषयों के एक भाग के रूप में पढ़ाया जा रहा है । पंजाब बोर्ड ने पाठ्य-विवरण में सहयोग को एक विषय के रूप में शामिल करने के लिए अपनी असमर्थता व्यक्त की है क्योंकि इससे विषयों की संख्या बढ़ जाएगी ।

(ग) जी, हां । इस मामले में सम्बोधित 107 विश्वविद्यालयों में से केवल 31 विश्वविद्यालयों ने इसका उत्तर दिया । अधिकांश विश्वविद्यालयों ने बताया है कि सहयोग कला, वाणिज्य और बी० एड० के संकायों के अन्तर्गत पढ़ाया जा रहा है । कुछ विश्वविद्यालयों में यह विषय स्नातक तथा स्नातकोत्तर, दोनों स्तरों पर पढ़ाया जा रहा है । केरल कृषि विश्वविद्यालय ने सूचित किया कि सहयोग में डिग्री पाठ्यक्रम आरंभ करने का उनका प्रस्ताव है । हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण विश्वविद्यालय और कालेजों में सहयोग के विषय को आरंभ करने के लिए अपनी असमर्थता के लिए खेद प्रकट किया है ।

विवरण

सिफारिशों का सारांश

1. (क) स्कूली पाठ्यचर्या के विभिन्न स्तरों पर सहयोग के विषय को पास करने के लिए उठाए जाने वाले ठोस कदम ।

(ख) स्कूल भंडारों, कैन्टीनों, थ्रिफ्ट और क्रेडिट सोसायटियों, उद्यानों होबी कार्यशालायों आदि के आयोजन और छात्र समुदाय में उनके बाल्यकाल से, ही, सहयोग की भावना को मन में बैठाने के लिए सहकारिता की रूप रेखाओं पर अन्य स्कूल समुदाय सेवाओं और कार्यकलापों को बढ़ावा देना ।

2. फालतू समय तथा व्यवहायिक पाठ्यक्रमों सहित स्नातक तथा मास्टर डिग्री के दोनों स्तरों पर कला तथा वाणिज्य पाठ्यक्रमों में एक वैकल्पिक विषय के रूप में अन्य पाठ्यक्रमों अर्थात् वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कृषि, विधि, समाजशास्त्र के भाग के रूप में सहयोग के विषय को शामिल करना ।

3. रोजगार अवसरों की व्यवस्था करना, रोजगार की गारंटी, निम्नलिखित में विभिन्न प्रोत्साहनों को तरजीह देना और उनकी व्यवस्था कराना :—

(क) सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए सहयोग के विषय को शामिल करना ।

(ख) भर्ती के लिए सहयोग के क्षेत्र में अर्हता रखने वाले छात्रों को वरीयता प्रदान करना ।

(ग) सहयोग में अर्हता प्राप्त छात्रों को सहकारिता के क्षेत्र में उपयुक्त रोजगार दिलाने में मदद करने के लिए

राज्य विश्वविद्यालयों के परामर्श से सलाहकार बोर्डों को गठित करना ।

(घ) छात्रवृत्तियां तथा पुरस्कार आरम्भ करना तथा सहकारिता पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे छात्रों में से प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती करना जिससे सहयोग के अध्ययन के लिए काफी संख्या में छात्रों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी ।

4. (क) सहयोग में अनुसंधान को प्रोत्साहन देना तथा काफी संख्या में अनुसंधान के लिए छात्रों को उत्तरोत्तर रूप में शिक्षावृत्ति प्रदान करने पर विचार करना ।

(ख) सहयोग के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा सहकारिता प्रशिक्षण संस्थाओं में सहयोग में अध्यक्षों की व्यवस्था करना ।

Operational costs of Railways

136. SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Railway Board has written to the State Governments requesting them to bear at least 50 per cent operational costs incurred in running certain economically non-viable section of Railways; and

(b) if so, what is the reaction of the State Governments in this regard?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI BANSI LAL): (a) Yes, Sir. Arising out of the recommendation of the Railway Reforms Committee, the Ministry of Railways have written to the State Governments concerned that they should agree either to the closure of certain uneconmic branch lines or share 50 per cent of the losses suffered by Railways in operating such of those lines as the State Governments concerned desire to be continued.

(b) Replies received so far are generally not in favour of either of the proposals.

Estimated demand of power during 1985-86

137. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) what is the estimated demand of power during 1985-86 and what is the basis thereof;

(b) what is the extent of power capacity likely to be achieved during 1985-86 as compared to that in 1984-85; and

(c) what steps Government propose to take to achieve the target for 1985-86?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER (SHRI ARUN NEHRU): (a) The anticipated energy requirement of the country for the year 1985-86 is 181 billion units, based on the actual consumption during the previous year suitably increased to take care of the power cuts/regularly measures, wherever applicable and allowing for a suitable rate of growth in power requirement.

(b) During 1985-86, it is programmed to commission new generating capacity of 4459.5 MW as compared to 3080 MW commissioned during 1984-85.

(c) Intensive monitoring is being done to achieve the targets for 1985-86.

Expert committee to ascertain the causes of accidents

138. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up an Expert Committee to ascertain and to analyse the "root cause" of the railway accidents and derailments instead of the present practice of inquiring into such accidents by the Accident Enquiry Committees;

(b) if so, with what results; and